RAJYA SABHA

Wednesday, the 7th January, \976/tlie 17 th Pausa, 1897 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Family Planning Programme during 1976

*31 SHRI SWAISINGH SISODIA :

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY:

SHRI SYED NIZAMUDDIN:

SMT. MARGARET ALVA:

SHRI GIAN CHAND TOTU:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to introduce some new incentives to popularise family planning programme in the country during the year 1976; and

(b) if so, what are the broad outlines ot the proposal?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) These will be finalized shortly.

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : यद्यपि स्वेच्छापूर्वक परिवार नियोजन की सफलता पर स्वास्थ्य मंत्रालय बधाई का पात्र है लेकिन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में आबादी का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि वर्तमान दर के हिसाब से भारत की आबादी सन् 2000 में 200 करोड़ होने का अंदाजा है। इससे पता लगता है सभी अन्य क्षेत्रों की सफलताएं बेकार सिद्ध हो सकती है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sawaisingh Sisodia.

कि स्वैच्छापूर्वक परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाने के बजाय कारगर रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिपालन हेतु वैधानिक आर्थिक अनिवार्यताओं के लिये हुए कड़े कदम राष्ट्र हित में उठाने का कोई प्रस्ताव इस सरकार के विचाराधीन है ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं माननीय सदस्य जब यह कहते हैं कि स्थिति बड़ी गम्भीर होती चली जा रही है। इसीलिए जहां स्वैच्छापूर्वक कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे वहां शायद कड़े कदम भी हमें सोचने पड़ें। मुझे आशा है जल्दी ही इस प्रकार के कुछ कदम हम उठावेंगे।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : परिवार नियोजन के कार्यक्रम में नई जान डालने के लिये इसको एक आन्दोलन के रूप में ले जाने की जरूरत है। इस संबंध में आपकी क्या कोई योजना है और अगर है तो उसकी क्या रूपरेखा है और इस बारे में आपने कोई कदम उठाया है ? सोचने वाली बात मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि स्वैच्छापूर्वक आपने कोई संकल्प लिया है और इस दिशा में कोई कदम उठाया है ?

डा० कर्ण सिंह : जन आन्दोलन की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है इसके बिना कभी सफलता नहीं मिल सकती। बहुत से कार्यक्रम हम अपना रहे हैं उनमें से कुछ कदम ये हैं। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं उन्हें हम इसमें जोड़ रहे हैं जैसे कि पंचायतें हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का हम परिवार नियोजन में सहयोग लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्ज हैं उन सभी का सहयोग लेने का यत्न कर रहे हैं। अभी-अभी यहां एक उत्सव हुआ था। इसी ढंग से जो वोलंटिरी संस्थाएं हैं उन को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो आर्गेनाइज्ड लेबर हैं वहां हम ने एक त्रिपक्षीय कमेटी बना दी है उसमें सरकार भी है, मजदूर भी है और मालिक भी है और उन को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के माध्यम से हम एक सारे देश में नया वातावरण बनाने का यत्न कर रहे हैं और विशेषकर शिक्षा संस्थाओं में भी हम परिवार नियोजन के महत्व पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा आन्दोलन देश में बनते-बनते कुछ समय

लगता है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हमने सिर्फ सोचा ही नहीं है हमने बहुत से कदम पिछले वर्ष उठाये भी हैं। उन कदमों की वजह से हमें परिवार नियोजन में कुछ सफलताएं मिली हैं, सफलताएं मिलनी शुरू हुई हैं। ये कदम और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: In view of the fact that so many incentives given earlier for the family planning programme have not been much successful because of maladministration of the programme, may I know whether his Ministry has examined this question? By maladministration I mean corruption in the administration of the family planning programme by the persons in charge of it in different States. If so, what steps are they going to take to stop such corrupt practice in future?

DR. KARAN SINGH: It is true that the success of any programme depends ultimately on its implementation. There have been, from time to time, certain complaints, but I think, by and large, it would not be correct to say that the entire programme has been riddled with corruption. There were certain complaints from time to time. Whenever such complaints come to our notice, we look into them, but in addition to that, what we are trying to do, and I think what the hon. Member is referring to, is to gear up the administrative machinery because merely having incentives and merely having programmes in Delhi and then not having them properly implemented is meaningless. So we are gearing up the administrative machinery. We are getting the State Governments much more actively involved in this entire programme. So far there was a view that this was the responsibility only of the Government of India because it was a Centrally-sponsored programme. We are now taking the line that although the Government of India is giving the money, this is a programme which essentially has got to be administered by the States and I am glad to be able to inform the House that in the last year, the performance of various States has been considerably better than i! was before, and our efforts to tone up the administration of the programme will continue.

SHRI SYED NIZAM-UD-DIN: For sometime past the Family Planning Department has been trying to lay stress on the sterilisation and operation side of the programme. But this has not found favour in the rural urea, in my opinion. Therefore, I would like to know from the hon. Minister if there will be a programme of family planning to be carried to the people in the rural areas with proper contraceptives so that conception is averted. Otherwise keeping in view the psychology of the people living in rural areas, just stopping child-birth does not find favour with them. Therefore, the emphasis should be laid on the other side of the family planning programme. What proposal do the Government have with regard to that?

DR. KARAN SINGH: Sir, our experience has been that even in the rural areas, sterilisation is becoming increasingly popular. But in addition to that, as the hon. Member has snid, there should be other methods. We are, therefore, also popularising lUDs and, in particular, what are known as the conventional contraceptives like the Nirodh. Nirodh is now being increasingly utilised in the rural areas. So we want to give the option to people to utilise either of these methods.

SHRI GTAN CHAND TOTU: Sir, may I know from the hon. Minister the reasons for the ineffectiveness and poor execution of this department in spite of the huge funds given for family planning?

DR. KARAN SINGH: Sir, I am afraid it is a loaded question. I do not accept the fact that the department's performance has not been good. In fact . . .

SHRI N. G. GORAY: Sir, we on this side are also interested in this.

MR. CHAIRMAN: These are the Members who are on the list. What can I do? I cannot avoid them.

DR. KARAN SINGH: I think that our programme has, in fact, in the last 20

years, some very substantial achievements to its credit. For example, according to our calculations, almost 23 million births, that is, 2.3 crore births, have been averted as a result of the programme. However, as I have said publicly and as I would repeat again, this is far from adequate to meet the growing requirements. Therefore, we will certainly try and improve the performance.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: In order to involve the people in the programme, has the Government any new strategy of involving political parties in the campaign? Also apart from incentives, would there be disincentives also?

DR. KARAN SINGH: Sir, I am happy to say that political parties are also beginning to get involved in this. If I may mention one, our own party, the party to which the Government belongs, for the first time in its Economic Policy Resolution passed a few days ago in Chandigarh, has a special paragraph on family planning. This, I think, is the beginning of what I hope will be adopted by every political party in this country because this is not a matter which should become a subject of controversy. It should be a national concensus. Secondly, in addition to incentives, we are considering the possibility j of introducing certain disincentives also.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इस देश के कुछ वर्गों ने धार्मिक आधार पर परिवार नियोजन का बहिष्कार किया है और उसका परिणाम यह है कि इस देश में समान रूप से परिवार नियोजन सब पर लागू नहीं हो रहा है ? अगर आप सन् 1971 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि जहां हिन्दुओं की पोपुलेशन 23.64 परसेन्ट बढ़ी है वहां क्रिश्चियन्स की 32.80 परसेन्ट और मोहमडन्स की 30.8 परसेन्ट बढ़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि परिवार नियोजन इस देश में समान रुप से लागू नहीं है। ऐसी स्थिति में जानना चाहता हूं कि जब सरकार के सामने जनगणना की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है तो आप इस परिवार नियोजन को समान रूप से सब पर लागू करने के लिए कम्पलसरी क्यों नहीं करते हैं और इसको सब के लिए कम्पलसरी बनाने में क्यों झिझकते हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग वर्गों की जनसंख्या कई कारणों से बढ़ गई है। उसमें कुछ तो आर्थिक कारण होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं-कहीं धर्म के नाम पर या और किसी चीज के नाम पर यह हुआ है। आज तक हमारा प्रयास केवल स्वैच्छा के ऊपर ही रहा है, इसलिए किसी के ऊपर दबाव डालने का कभी कोई सवाल नहीं है...

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्यों ?

डा० कर्ण सिंह : मेरी अर्ज सुनिए। आज तक यह रहा है—वस्तुस्थिति आपको बतला रहा हूं—कि हमने अभी तक इसको कम्पलसरीली लागू करने का विचार नहीं किया और मैं स्पष्ट कर दूं अध्यक्ष महोदय, कि इस समय कोई ऐसा कानून, राष्ट्रीयस्तर के ऊपर, बनाने की अभी हमारी योजना नहीं है...

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्यों नहीं है ? कारण बताइए।

डा० कर्ण सिंह : इसलिए नहीं है कि कानून बनाने में कई कठिनाइयां भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि कभी नहीं बनेगा कानून। राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ करना चाहें तो कदम उठा सकती हैं मगर हमने देखा है कि बावजूद इसके, अगर कोई अनुशासन अपने ऊपर न करे तो जबर्दस्ती लगाना पड़ता है। तो शायद वह भी स्थिति आ जाए। लेकिन इससे पहले कि हम जबर्दस्ती कानून द्वारा प्रतिबंध लगाएं हम अब स्वयं, स्वैच्छा से, एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं जहां कि हम इन्सेंटिव और डिसइंसेंटिव का पैकेज दे रहे हैं। इसको देखते हैं कि कुछ वर्षों कैसे काम चलता है और फिर अगर स्पष्ट हो जाए कि तब भी नहीं हो रहा है तो शायद, जैसा त्यागी जी इशारा दे रहे हैं, हो सकता है हमें कानून बनाना पड़े और जाहिर है जो कानून बनेगा वह सब पर लागू होगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि हमारा टार्गेट क्या था ? क्या उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है या नहीं किया ? अगर नहीं किया तो उसका क्या कारण है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते हैं कि अभी तक ज

ऐच्छिक रूप से हमने फैमिली प्लानिंग का कार्य किया है यह जो शिक्षित वर्ग है जो बुद्धिवादी वर्ग है, उन तक सीमित रहा है लेकिन जो ऐसे वर्ग हैं जो कि पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी बहुत बहुत कम है, ऐसे लोगों में परिवार नियोजन का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है ? क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते हुए यह करेंगे कि किसकी कितनी आमदनी है उसके अनुसार उसके ऊपर फैमिली प्लानिंग को कंपलसरी करना अनिवार्य होगा, इसकी तरफ वे कदम उठाएंगे ? अगर उठाएंगे तो कब तक ?

एक माननीय सदस्य : क्या आप चाहती हैं ज्यादा आमदनी वाले के ज्यादा बच्चे हों ?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो कम आमदनी वाले हैं उनके ऊपर कंपलसरी जरूर करना चाहिये क्योंकि उनके ऊपर भार ज्यादा पड़ता है ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न पूछे हैं । एक तो टार्गेट के, लक्ष्य के, विषय में उन्होंने पूछा । तो टार्गेट की स्थिति यह है कि पिछली बार तो कई टार्गेट बने, कई बिगड़े । लेकिन इस समय का टार्गेट यह है कि प्रति वर्ष हजार में एक, बस् पर थाउजेंड, हम बर्थ रेट में घटौती करें। तो इस समय, जब से हमारी पंचम प्रथम वर्षीय योजना आरम्भ हुई, हमारा अंदाज है कि प्रति हजार 35 अगर हमारी बर्थ रेट थी तो अब हमारा लक्ष्य यह है कि अगले 10 वर्षों में एक-एक प्रति हजार के हिसाब से कम होनी चाहिय, गर्ज कि 30 प्रति हजार हो जायेगी पांचवें प्लान के अंदर और उससे अगले प्लान में 25 प्रति हजार हो जायेगी। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये बहुत कार्य की जरूरत है । मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार से इस लक्ष्य तक हम न पहुंचेंगे इसीलिये रफ्तार को थोड़ा सा और तेज किया जाये । दूसरी बात उन्होंने ठीक कही कि इस समय गांव-गांव तक जन-साधारण में जिस तरह इस परिवार नियोजन का कार्यक्रम पहुंचाना चाहिये था वह नहीं पहुंचा, शहरों में पहुंचा है लेकिन जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, दूर-दराज इलाके में रहने वाले है उन तक नहीं पहुंचा है । यह हमारी कमजोरी रही है। इसके कई कारण हैं और किसी समय इस पर बहस होगी तो उस समय बतला सकता हूं । अभी तो हम यह विशेष प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने भी दूर-दराज के इलाके हैं, जितने भी पिछड़े इलाके हैं, जितने भी गरीब इलाके हैं, वहां पर हम इस संबंध में अधिक प्रचार करें और प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से और उप-केन्द्रों के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं ।

एक बात और कर रहे हैं और वह यह है कि जितने भी हमारे मलेरिया और स्मालपाक्स को दूर करने के कार्य में लगे हुए वर्कर्स हैं, उनको और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वर्करों का एकीकरण करके उनके माध्यम से हर एक नागरिक तक यह कार्य पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ।

जहां तक कम्पलशन का सवाल है, उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कानून हो, वह सब पर एक जैसा हावी होना चाहिये । यह बात नहीं हो सकती है कि अमीर पर उसका असर न हो और गरीब पर ज्यादा हो। इसलिये हम इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि सारे देश के ऊपर इसका असर समान रूप से पड़े ।

आपने यह ठीक ही कहा है कि ज्यादा बच्चे होने से गरीबों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है और इसीलिये हमारा यह यत्न है कि हम इस बारे में भरसक कोशिश कर रहे हैं कि यह कार्य उन तक पहुंच सके।

SHRI N. G. GORAY: Sir, I wonder whether we are going to give up this attitude of complacency at all. If I may point out, the capitalist countries as well ;is ihe communist countries and even some of the developing countries have controlled their population and they have succeeded in it. I do not know why it is that only India is lagging behind though for us it is a question of life and death. Sir, I am not exaggerating this. I say this because unless we check our population, all

our plans, whatever be our suecess, will go haywire and the population growth must be checked. I would like to ask him why he is going about beating about the bush. There is hardly any sector of public life which is not under the control of <he government now and everybody is under the control of the government, whether he is a farmer or whether he is a labourer or whether he is a midle-class employee. Now, if you take this face into consideration, you will agree that almost everybody can be brought under this law, if you want to have it. that unless he restrict his family, it will not be possible for him to get any incentive, whether he is working in the agricultural sector or in the labour sector or in the government sector or in the public sector or in the private sector or whether he is self-employed. You can say that that anybody who has more than three children will not be given any bank credit or that he will not be I given fertilizers or he will not be given irrigation facilities and so on. Like thai you can cover the entire population. Only you have to link up this particular problem with the facilities that he is getting. If you can do that, 1 suppose it will be possible for you to progress at a faster pace.

DR. KARAN SINGH: I entirely agree with the honourable Member who has pointed out the gravity of the situation. In fact, far from being complacent—the honourable Member would perhaps have noticed—during the last two years hardly a day has passed when I did not press the tremendous importance of family planning and I am glad to say that an atmosphere has now been created in this country where the importance of family planning and population limitation is now being very widely accepted. Now, the point is how to do it or achieve it. Sir, if you give me two more minutes, I will be able to explain . . .

MR. CHAIRMAN : You have already taken about twenty minutes.

DR. KARAN SINGH: I am sorry, Sir. Anyway, I would like to say that there are various aspects of the question. There is the question of raising the age of marriage . . .

SHRI N. G. GORAY : That has also been delayed.

DR. KARAN SINGH: Sir, I entirely agree with him that if the age of marriage is raised and if the law in regard to that is effectively implemented, that can be one important factor. Then, Sir, there is the question of this package of incentives and disincentives and there are several ways. There are many ways and there are fiscal measures, there are tax measures and there are other ways in which the vast section of the population can be covered by this and the package of incentives and disincentives that I am planning will cover many of the points that the honourable Member has mentioned.

SHRI IANARDHANA REDDY : Sir, the honourable Member was telling, in the course of his reply, that they want to propagate family planning through the educational institutions. I would like to know whether they have got any definite programme. I also want to know whether the honourable Minister is aware of the fact that certain Universities have taken up population studies and extension programmes and the Tirupati and the Venkateswara Universities have taken up these things. You know it, Sir. I want to know whether he is aware of this and whether the Government has any plans to assist such programmes in other Universities also.

DR. KARAN SINGH : Sir, I am in close touch with my colleague, the Education Minister and the Deputy Education Minister and we are trying to involve the educational institutions in several ways. One is the primary school teacher because we feel that the primary school teacher is one of the important persons who reach out into the rural areas and if the primary school teachers can be motivated and if they can be motivated not only in family planning programmes, but also in some simple health services, that can bring about a revolution in the village areas in the country. That is one aspect.

As far as Universities are concerned, we welcome the introduction of population courses. We are also in touch with the N.C.E.R.T. that text-books should contain important information regarding population, so that the concept of family limitation is woven into the entire curriculum without, unnecessarily, having to be taught as a separate subject. We are fully aware of this aspect.

MR. CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA : Is the hon. Minister aware. . .

(Interruptions)

AN HON. MEMBER :He is not entitled to ask questions on family planning . . .

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA : J am very much yll'ected . . . *(Interruptions).* Is Iw more qualified to speak on family planning than myself?. . . . *(Interruptions).* Sir, it is bad enough to produce seven children and then after if you ask supplementaries this is worse still . . .

(Interruptions)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब फैमिली ही नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग क्या होगी ?

SHRI BHUPESH GUPTA : Now, Sir, may I ask whether the hon. Minister is aware that some people, political parties specially Jana Sangh, have made this ques tion of family planning a political issue *1* Specially, recently in a conference of Arya Santaj which was held in Delhi, there were tirades against family planning and the ti-rades were all made from a communal angle. Is he aware of that ? If this issue is sought to be exploited politically in thi? manner, communally, then it will be more difficult to propagate the ideas of family planning or to ensure the success of family planning. May I know what steps does the Government propose to take in order to deal uitli such kind of propaganda ?

SHRI OMPRAKASH TYAGI: Sir, or» apoint of order.

MR CHAIRMAN : If it is *galat,* then he will reply.

DR. KARAN SINGH : It would indeed be utterly unfortunate, as 1 mentioned in reply to an earlier question, if this matter were to be the subject of political contro-versy. My own view is that as there is no controversy on the importance of defence—everybody agrees that the country must be defended—similarly there must be no controversy on the question of family planning. Sir. 1 am not aware whether the Arya Samaj said anything about this in; this manner, but if they have. Sir, it is very unfortunate.

SHRI OMPRAKASH TYAGI: Not at all, I am the General Secretary of that Society.

DR. KARAN SINGH : I am happy to learn that they did not. But if, as some hon. Members said, it is so, it is unfortunate.

MR. CHAIRMAN : Next question.

Area under cotton cultivation and production of Kapas

*32. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRI-GATION be pleased to state the area under cotton cultivation in the country and the estimated production of kapas for t he-year 1975-76. in the cotton growing Sta-tes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P.
SHINDE): According to the all-India first estimate of cotton. 1975-76, area under cot-ton has been placed at 6.05 million hectares compared to the corresponding estimate of

मैं कहना चाहता हूं कि वह गलत बोल रहे हैं। आर्य समाज में कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई ।

5.54 million hectares in 1974-75, showing an increase of 9.2 per cent. Past expe-